

Roll No. ....

**B.A.-10 (Bachelor of Art)**  
**First Year, Examination 2012**  
**PA-02**  
**Public Administration in India**  
भारत में लोक प्रशासन

**Time: 3 Hours**

**Max. Marks: 60**

समय: 3 घंटे

अधिकतम अंक: 60

Note: The question paper is divided into three sections 'A' 'B' and 'C'. Attempt questions of each section according to given instructions.

नोट: यह प्रश्नपत्र क, ख और ग तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**Section A खण्ड-क**

**Long Answer Questions दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

**Note: Answer any two questions. Each question carries 15 marks**  
**15X2=30**

नोट:— किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

Q.1 Discuss the composition, functions and powers of the Union Council of Ministers.

संघीय मन्त्री परिषद के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।

Q.2 What is public corporation? Explain their distinctive characteristics. For what purposes are they created?

लोक निगम क्या है? उसके स्पष्ट लक्षणों की व्याख्या कीजिए। किन उद्देश्यों के लिए इनकी रचना की जाती है?

Q.3 Discuss the Various methods of recruitment to civil service.  
लोक सेवा में भर्ती की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए।

Q.4 Discuss the parliamentary control over Public Administration.  
लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विवेचना कीजिए।

### **Section B खण्ड—ख**

#### **Short Answer Questions लघु उत्तरीय प्रश्न**

**Note: Answer any four questions. Each question carries 05 marks  
5X4=20**

नोट:— किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 05 अंक का है।

Q.1 Describe the Emergency Power of the President of India.  
भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Q.2 The Role of Prime Minister's in contemporary politics.  
वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका।

Q.3 What do you understand by Budget?  
बजट से आप क्या समझते हैं?

Q.4 Describe the functions of Public Service Commission.  
लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए।

Q.5 Evaluate the various tools of Judicial control over Administration.  
प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न यंत्रों का मूल्यांकन कीजिए।



- a. Article 356    b. Article 75    c. Article 76    d. Article 61  
 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग  
 चलाया जा सकता है—  
 क. अनुच्छेद 356    ख. अनुच्छेद 75    ग. अनुच्छेद 76    घ. अनुच्छेद 61

Q.3 Grant provided to state, from Indian Consolidated Fund on the recommendation of Central Government, by-

- a. Planning Commission    b. Finance Commission  
 c. Public Account Committee    d. Estimate Committee  
 केन्द्रीय सरकार, जिसकी संस्तुतियों के आधार पर भारत की संचित निधि से  
 राज्यों को सहायता अनुदान देती है, वह है—  
 क. योजना आयोग    ख. वित्त आयोग  
 ग. लोक लेखा समिति    घ. प्राक्कलन समिति

Q.4 Who directs the name of Chairman of Indian Parliamentary Public Account Committee

- a. Prime Minister    b. President  
 c. Speaker of Lok Sabha    d. Speaker of Rajyasabha  
 भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम-निर्देशित  
 करता है—  
 क. प्रधानमंत्री    ख. राष्ट्रपति  
 ग. लोकसभा का अध्यक्ष    घ. राज्य सभा का सभापति

Q.5 Which one will not be sufficient base for declaration of National Emergency-

- a. war    b. External Attack    c. Armed revolt    d. Internal violence  
 निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए  
 पर्याप्त आधार नहीं माना जाएगा—  
 क. युद्ध    ख. वाहय आक्रमण    ग. सशक्त विद्रोह    घ. आन्तरिक उपद्रव

**Write true/false against the following.**

निम्नलिखित के सामने सत्य/असत्य लिखिए।

Q.6 Prime Minister and his council of ministers are real head in Union executive T/F

भारत में संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री व उसका मंत्रीपरिषद होता है।

Q.7 Judicial control provides more legitimacy on Administration.

T/F

प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण उसको औचित्यपूर्ण बनाता है।

Q.8 Right of Information Act passed in 2006.

T/F

सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ।

Q.9 One new All India service can be constructed by proposal of council of State T/F

एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है।

Q.10 Jawahar Lal Nehru said to Government of India Act 1935 'A new authority letter of slavery.'

T/F

गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 को जवाहर लाल नेहरू ने 'दासता का एक नया अधिकार पत्र' कहा था।